



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 2010/माघ 23, 1931

No. 291]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 2010/MAGHA 23, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2010

का.आ. 342(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन जोन के रूप में घोषित किया था और उक्त जोन में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तारण, प्रचालन और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे ;

और, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा उक्त राज्य क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र में बालू के खनन पर उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा अधिरोपित किए गए निर्बंधनों और द्वीप समूह में उपलब्ध वैकल्पिक निर्माण सामग्रियों की कमी के कारण उक्त राज्य क्षेत्र की स्थानीय जनता द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में अपने तारीख 7 मई, 2005 के आदेश के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बालू के खनन के संबंध में आदेश पारित किए हैं ;

और, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई है ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों की प्रभावी करने की दृष्टि से उक्त अधिसूचना को संशोधित किया जाना चाहिए ;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में यह उपबंध है कि उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी जब कभी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उपरोक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करने के लिए उपरोक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की उक्त अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा 2 के उप-पैरा (ix) के परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निर्माण प्रयोजन के लिए बालू के खनन की अनुज्ञा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल द्वारा -
(1) मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन ; (2) सचिव, पर्यावरण विभाग (3) सचिव, जल संसाधन विभाग ; और (4) सचिव, अंडमान लोक निर्माण विभाग से मिलकर गठित समिति द्वारा मामला दर मामला आधार पर दी जा सकेगी :

परन्तु यह और कि खनन की जाने वाली बालू की कुल मात्रा 12,852 घन मीटर की उठाई न गई ऐसी बालू की मात्रा सहित, जिसको उठाए जाने की विधिमान्यता 31 दिसम्बर, 2008 को समाप्त हो गई थी और अब 30 जून, 2010 तक नवीकृत की गई है, 30 जून, 2010 तक की अवधि के लिए 11,291 घन मीटर से अधिक अनुज्ञेय नहीं होगी और 24,143 घन मीटर बालू की कुल मात्रा का खनन के उन क्षेत्रों में किया जाएगा जिन्हें सागर प्रबंधन संस्थान चेन्नई द्वारा संबंधी क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है और वह बालू के पुनर्भरण या जमाव की दर पर आधारित होगा :

परन्तु यह भी कि बालू के खनन के संबंध में इस उप-पैरा के अधीन दी जाने वाली मंजूरी खनन योजनाओं पर आधारित होगी और इसमें संवेदनशील तटीय पारिप्रणालियों जिसके अंतर्गत प्रवाल, कछुए, मगरमच्छ, पक्षियों के विश्रामस्थल तथा संरक्षित क्षेत्र हैं, को नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय अनुबोधित होंगे :

परन्तु यह और भी कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किए गए खनन क्रियाकलापों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित की जाएगी और निगरानी समिति में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पर्यावरण और वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर और अंडमान निकोबार के एक गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे और निगरानी रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय को त्रैमासिक रूप से भेजी जाएगी।”;

(ख) “तटीय विनियमन क्षेत्र-IV अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विषयक” शीर्ष के अधीन उपाबंध-1 की मद (iv) की उप-मद (ख) में “31 दिसम्बर, 2009” अंकों और शब्द के स्थान पर “30 जून, 2010” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. जेड-12011/2/96-आईए-III]

डॉ नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक ‘जी’

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 114 (अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया :

1. का.आ. 595(अ), तारीख 18 अगस्त, 1994
2. का.आ. 73(अ), तारीख 31 जनवरी, 1997
3. का.आ. 494(अ), तारीख 9 जुलाई, 1997
4. का.आ. 334(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1998
5. का.आ. 873(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1998
6. का.आ. 1122(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1998
7. का.आ. 998(अ), तारीख 29 सितम्बर, 1999
8. का.आ. 730(अ), तारीख 4 अगस्त, 2000
9. का.आ. 900(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2000
10. का.आ. 328(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2001
11. का.आ. 358(अ), तारीख 3 अक्टूबर, 2001
12. का.आ. 550(अ), तारीख 21 मई, 2002

13. का.आ. 1100(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2002
14. का.आ. 52(अ), तारीख 16 जनवरी, 2003
15. का.आ. 460(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2003
16. का.आ. 635(अ), तारीख 30 मई, 2003
17. का.आ. 636(अ), तारीख 30 मई, 2003
18. का.आ. 563(अ), तारीख 24 जून, 2003
19. का.आ. 838(अ), तारीख 24 जुलाई, 2003
20. का.आ. 86(अ), तारीख 25 जनवरी, 2005
21. का.आ. 108(अ), तारीख 13 जुलाई, 2006
22. का.आ. 451(अ), तारीख 26 मार्च, 2007

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2010

S.O. 342(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.114 (E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas the Andaman and Nicobar Administration of the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands has drawn the attention of the Central Government to the difficulties being faced by the local population of the said Territory due to lack of alternative construction materials available in the Islands and the restrictions imposed by the aforesaid notification on mining of sand in the Coastal Regulation Zone in the said Territory;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court *vide* its Order dated 7th May, 2005 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 has passed Orders on mining of sand in Andaman and Nicobar Islands;

And whereas the issue has been examined by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said notification should be amended with a view to give effect to the aforesaid Orders of the Supreme Court;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that notwithstanding anything contained in sub-rule (3), wherever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the said requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:—

In the said notification—

(a) in paragraph 2, in sub-paragraph (ix), for the provisos, the following provisos shall be substituted namely:—

“Provided that in the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands, mining of sand may be permitted for construction purpose on a case to case basis by a committee constituted by the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands consisting of — (1) the Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration; (2) Secretary, Department of Environment; (3) Secretary, Department of Water Resources; and (4) Secretary, Andaman Public Works Department :

Provided further that the total quantity of sand to be mined shall not exceed 11,291 cubic metres permissible for the period up to the 30th June, 2010 together with the unlifted quantity of 12,852 cubic metres of sand whose validity of lifting had expired on the 31st December, 2008 and is now renewed till the 30th June, 2010 and this mining of a total quantity of 24,143 cubic metres of sand shall be undertaken only in those areas which have been identified as accreting areas by the Institute for Ocean Management (IoM), Chennai and will be based on rate of replenishment or deposition of sand :

Provided also that the permission as may be granted under this sub-paragraph for mining of sand shall be based on mining plans and shall stipulate sufficient safeguards to prevent damage to the sensitive coastal eco-system including corals, turtles, crocodiles, birds nesting sites and protected areas :

Provided also that a monitoring Committee shall be constituted for monitoring the mining activity and the environmental safeguards taken, by the Union Territory Administration. The monitoring Committee shall comprise of representatives from the Union Territory Administration, Regional Office of

the Ministry of Environment and Forests, Bhubaneswar and a Non-Governmental Organization based at Andaman and Nicobar and the monitoring report shall be sent quarterly to the Ministry of Environment and Forests.”;

(b) In Annexure-I, under the heading “CRZ-IV relating to the Andaman and Nicobar Islands,” in item (iv), in sub-item (b), for the figures, letters and words “31st day of December, 2009”, the figures, letters and words “30th June, 2010” shall be substituted.

[F. No. Z-12011/2/96-IA.III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist ‘G’

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991 and subsequently amended *vide* notifications :

1. S.O. 595(E), dated 18th August, 1994
2. S.O. 73(E), dated 31st January, 1997
3. S.O. 494(E), dated 9th July, 1997
4. S.O. 334(E), dated 20th April, 1998
5. S.O. 873(E), dated 30th September, 1998
6. S.O. 1122(E), dated 29th December, 1998
7. S.O. 998(E), dated 29th September, 1999
8. S.O. 730(E), dated 4th August, 2000
9. S.O. 900(E), dated 29th September, 2000
10. S.O. 329(E), dated 12th April, 2001
11. S.O. 988(E), dated 3rd October, 2001
12. S.O. 550(E), dated 21st May, 2002
13. S.O.1100(E), dated 19th October, 2002
14. S.O. 52(E), dated 16th January, 2003
15. S.O. 460(E), dated 22nd April, 2003
16. S.O. 635(E), dated 30th May, 2003
17. S.O. 636(E), dated 30th May, 2003
18. S.O. 563(E), dated 24th June, 2003
19. S.O. 838(E), dated 24th July, 2003
20. S.O. 86(E), dated 25th January, 2005
21. S.O. 108(E), dated 13th July, 2006
22. S.O. 451(E), dated 26th March, 2007